कोयतुरो की बुलंद आवाज़

कोयतुर टाइम्स

KOYTUR TIMES
www.koyturtimes.com

सुविचार -
कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता.
- राल्फ वाल्डो एमर्सन

गुरुवार 09 जनवरी 2025 RNI: UDYAM-CG-11-0005844 website: koyturtimes.com

प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा एग्जाम वॉरियर्स आर्ट फेस्टिवल, तनाव मुक्त परीक्षा के संदेश पर जोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कला के माध्यम से परीक्षा के तनाव से उबरने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता और कला के जरिए परीक्षा के तनाव को कम करने का यह प्रयास प्रशंसनीय है। नई दिल्ली के शांतिपथ पर आयोजित एग्जाम वॉरियर्स आर्ट फेस्टिवल में कुल 30 विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 4,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना और उन्हें परीक्षा के दबाव से मुक्त करने के लिए प्रेरित करना था। इस आयोजन के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा: "रचनात्मक सफलता के माध्यम से परीक्षा के तनाव से उबरना! यह देखकर खुशी हुई कि इतने सारे युवा एक साथ आए और तनाव मुक्त परीक्षा का एक मजबूत संदेश देने हेतु कला की शक्ति का उपयोग किया।" फेस्टिवल में विद्यार्थियों ने पेंटिंग, स्केचिंग, और अन्य कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता को अभिव्यक्त किया। इन रचनात्मक प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि कला और रचनात्मकता परीक्षा के दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह फेस्टिवल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रेरित पुस्तक "एग्जाम वॉरियर्स" के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और इसे उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रेरित करना है। यह आयोजन शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने और विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

व्यापार उपक्रम को पेगाट्रॉन इंडिया को स्थानांतरित करने को मंजूरी दी

संवाददाता | नई दिल्ली

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) द्वारा पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पेगाट्रॉन इंडिया) की कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण और टेल कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईएल) के व्यापार उपक्रम को पेगाट्रॉन इंडिया को स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:(a) टीईपीएल ने दो किस्तों में पेगाट्रॉन इंडिया की अधिकांश हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव रखा है। (b) टीईपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (यानी, टीईएल) ने अपने व्यापार उपक्रम को पेगाट्रॉन इंडिया में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। टीईपीएल टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे बड़े ग्राहकों के लिए उच्च स्तर के सटीक घटकों के निर्माण की विशेषज्ञता प्राप्त है। यह स्मार्टफोन के लिए स्मार्टफोन एनक्लोजर (यानी, फोन का फ्रेम जिस पर स्मार्टफोन के अन्य घटक/उप-असेंबली असेंबल किए जाते हैं) बनाती है। टीईपीएल, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस [जिसे पहले विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था] के माध्यम से स्मार्टफोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सेवाओं (ईएमएस) के प्रावधान में भी संलग्न है। इसके अलावा, टीईपीएल, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीईएल के माध्यम से स्मार्टफोन के लिए ईएमएस प्रदान करने के लिए एक ग्रीनफील्ड सुविधा स्थापित कर रही है। पेगाट्रॉन इंडिया पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। पेगाट्रॉन इंडिया एक वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड के लिए स्मार्टफोन के लिए ईएमएस सेवाओं के प्रावधान में संलग्न है और भारत में स्मार्टफोन ब्रांड को बेचने के अलावा अपने उत्पादों को उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के विभिन्न देशों को निर्यात करती है।

मुख्यमंत्री से महाप्रबंधक रेलवे ने की सौजन्य मुलाकात

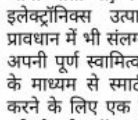

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने सौजन्य मुलाकात कर नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रायपुर श्री दयानंद भी उपस्थित थे।

ब्रेकिंग न्यूज भारतीय प्रवासियों और स्थानीय समुदाय के लगभग 150 आगंतुकों का स्वागत किया

आईएनएस तुशिल ने सेनेगल में डकार की अपनी यात्रा पूरी की

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के नवीनतम गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देते हुए सेनेगल के डकार में अपनी प्रारंभिक बंदरगाह यात्रा पूरी कर ली है। जहाज के कप्तान पीटर वर्गीस ने डकार में अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान दोनों देशों के मध्य नौसेना सहयोग को बढ़ावा देने और साझा समुद्री सुरक्षा गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए सेनेगल नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ, रियर एडमिरल अब्दु सेने के साथ बातचीत की। इस यात्रा में एक विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय (एसएमईई) प्रावधान भी किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के निशार-मित्र टर्मिनल का प्रदर्शन और सेनेगल के योग एसोसिएशन तथा नौसेना कर्मियों का एक संयुक्त योग सत्र शामिल था। जहाज ने भारतीय प्रवासियों और स्थानीय समुदाय के लगभग 150 आगंतुकों का स्वागत किया, जो इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। आईएनएस तुशिल ने अपने प्रस्थान से पहले सेनेगल के नौसैन्य जहाज पीएचएम निआनी के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज (पैसेक्स) करके दौरे का समापन किया। यह यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालती है और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय नौसेना के नवीनतम गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया

नई दिल्ली: भारत सरकार ने वर्ष 2025 के कैलेंडर के लिए "जनभागीदारी से जनकल्याण" को मुख्य थीम के रूप में चुना है। रेल भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कैलेंडर का अनावरण किया। उन्होंने पिछले एक दशक में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी शासन के स्पष्ट प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण और देश में बुनियादी ढांचे के विकास में परिवर्तनकारी शासन की भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू, पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक श्री धीरेंद्र ओझा और केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक श्री योगेश बावेजा भी उपस्थित थे। देश वर्ष 2014 से 2025 तक सुशासन के 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। भारत सरकार का कैलेंडर 2025 इस परिवर्तनकारी शासन को उजागर करने का प्रतीक है। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित यह कैलेंडर समावेशिता, पारदर्शिता और भागीदारीपूर्ण शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। चित्रों के माध्यम से देश की विकास यात्रा और जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि देश की ताकत लोगों की सामूहिक ऊर्जा और प्रयासों में निहित है। स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी पहलों में नागरिक भागीदारी की अहमियत को रेखांकित किया गया है। कैलेंडर 'सर्वेषां मंगलं भूयात्' के आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ होता है। इसमें कृषि, महिला सशक्तीकरण, युवा और राष्ट्र की प्रगति को दर्शाया गया है। "अन्न का वर्धन हो", "शक्ति रूपेण संस्थिता" जैसे मंत्रों के माध्यम से महिलाओं को शक्ति और युवाओं को ज्ञान प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास को "राष्ट्र समृद्धि में पनपता है" के मंत्र से जोड़ा गया है। मई में स्वच्छता को "आंतरिक शुद्धता बाहरी स्वच्छता की ओर ले जाती है" के आदर्श वाक्य से संबोधित किया गया है। जुलाई स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को प्राथमिकता देता है। स्वतंत्रता दिवस के महीने में एक स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उद्यमशीलता और भारतीय अर्थव्यवस्था के योगदान को "उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि" के माध्यम से चित्रित किया गया है। एकता दिवस सरदार पटेल को समर्पित है। नवंबर का महीना जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है, जो मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। दिसंबर का महीना तकनीकी नवाचार और शासन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मानवीय उपयोग पर केंद्रित है। इसमें "अपरिमितं भव्यम्" का संदेश दिया गया है, जो भविष्य में असीम संभावनाओं को इंगित करता है। यह कैलेंडर 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और इसकी पहुंच ग्राम पंचायतों तक है। यह समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और सरकार की पहलों को जमीनी स्तर तक ले जाने का माध्यम बनता है। यह न केवल एक व्यावहारिक संसाधन है, बल्कि राष्ट्र की एकता और शक्ति का प्रतीक भी है। इसके माध्यम से सरकार की पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर होती है। कैलेंडर भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों की सामूहिक शक्ति और साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह परिवर्तनकारी शासन और जनभागीदारी की ताकत को रेखांकित करता है। इसके माध्यम से सरकार देश को उज्जवल और समावेशी भविष्य की ओर प्रेरित करने का संदेश देती है।

राज्य स्तरीय वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने की। इस अवसर पर भारतीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ एंटरप्राइज डिवीजन के निदेशक श्री सोमनाथ जाना एवं वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी श्री सुप्रिया साधु खान ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती रोक्तिमा यादव ने वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सर्वेक्षण राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में पंजीकृत इकाइयों का विस्तृत आकलन करने में सहायक होगा। इससे राज्य के आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। कार्यशाला के दौरान निदेशक श्री सोमनाथ जाना ने औद्योगिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया और उसके विभिन्न खंडों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं व्यावहारिक प्रशिक्षण में सर्वेक्षण के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से प्रतिभागी आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक श्री नारायण बुलीवाल, संयुक्त संचालकगण, उप संचालकगण,सहायक संचालकगण सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक सहित संचालनालय के अधिकारी – कर्मचारी उपस्थित थे।

सत्यवती को अब नहीं होगी चलने में परेशानी

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बेहतर डॉक्टरों की टीम के साथ मुंगेली जिला अस्पताल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लाक के ग्राम भदौरा निवासी सत्यवती चतुर्वेदी के बोन ट्यूमर बीमारी का सफल ऑपरेशन किया गया। सत्यवती पिछले 06 माह से बाएं पैर की एड़ी के ऊपर सूजन और दर्द के कारण काफी परेशान थी। उन्होंने आस-पास इलाज कराया पर कोई समाधान नहीं मिला। आर्थिक तंगी के कारण महंगे निजी अस्पतालों में इलाज करना संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने जिला चिकित्सालय मुंगेली में संपर्क किया। यहां पर अस्थि रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच एवं एक्सरे किया गया और उनके बाएं पैर की फीबुला हड्डी में बोन ट्यूमर बीमारी का होना पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभात चंद्र प्रभाकर ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ. एम.के.राय के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा पूरी संवेदनशीलता एवं कुशलतापूर्वक सत्यवती के इस जटिल हाई रिस्क सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और सत्यवती ने बताया कि पहले चलने में काफी परेशानी होती थी, पैर में दर्द रहता था। निजी अस्पताल में इलाज कराने से लाखों रुपए खर्च होते, लेकिन जिला चिकित्सालय में उनका बिना पैर काटे सफल ऑपरेशन हुआ है। इससे वह काफी खुश है। उन्होंने जिला चिकित्सालय की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वह अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री गिरीश कुर्रे ने बताया कि सत्यवती को स्वास्थ्य लाभ के लिए रेड क्रॉस और जन औषधि के माध्यम से 05 हजार रुपए का चेक भी प्रदान किया गया।

अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने हमारी सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

Koytur times

बालोद छत्तीसगढ़: अटल जी की स्मृति में वर्ष 2025 को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष गुणवत्तायुक्त विकास कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास और सबका विश्वास मूलमंत्र के साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के विकास और निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें और विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बालोद जिले के ग्राम जुगेरा में आयोजित 141 करोड़ रूपए के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई संसाधन और सड़कों के रखरखाव पर फोकस करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने प्रतिबद्ध है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जिसे रामराज्य कहा गया है, वही तो सुशासन है। सुशासन का सूर्योदय हो गया है, यह सब आप लोगों के स्नेह और अपार जनसमर्थन से यह संभव हो सका है। हमें विश्वास है कि आप सबका भरोसा अटूट रहेगा। सभी मिलजुलकर विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। पक्का छत वाले मकान निर्माण की योजना प्रधानमंत्री आवास के तहत बालोद जिले में 31 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। इनमें आधे से अधिक आवास बन गए हैं। शेष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने नए आवास में प्रवेशित हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

तेंदूपत्ता खरीदी की दर में प्रति मानक बोरा 15 सौ रूपए की अतिरिक्त वृद्धि

मुख्यमंत्री साय ने बालोद जिले के ग्राम जुगेरा में आयोजित कार्यक्रम में 141 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर बालोद में 400 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण और जुगेरा स्थित बंजारी माता मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए डोम सेट निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बालोद में नालंदा परिसर का निर्माण होगा, इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर के रूप में सेवा दे रही बालोद के ग्राम जमरूवा निवासी वीणा साहू की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बालोद जिले में बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता हितग्राही हैं, हमने उनके हित में तेंदूपत्ता खरीदी की दर में प्रति मानक बोरा 15 सौ रूपए की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए 5500 रूपए प्रति मानक दर से खरीदी सुनिश्चित की।

डेढ़ लाख से अधिक किसानों के खाते में 223 करोड़ रूपये

हमने डौंडीलोहारा विकासखंड के मटियामोती जलाशय के नहरों का लाइनिंग मरम्मत और पुर्ननिर्माण के लिए भूमिपूजन किया है। करीब 30 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इस नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना से बालोद जिले के करीब डेढ़ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उनके खाते में 2023-24 में बेचे गए खरीफ सीजन के धान की राशि 686 करोड़ रूपये अंतरित की गई है, इससे किसानों में समृद्धि आयी है। किसान खुशहाल हुए हैं। हमारा मानना है कि जब हमारे अन्नदाता खुशहाल होंगे तो सभी का जीवन सुखमय रहेगा। बालोद जिले में डेढ़ लाख से अधिक किसानों के खाते में 223 करोड़ रूपये बकाया बोनस की राशि भी हमने गत वर्ष दिया है। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वाली श्री विष्णु देव साय की सरकार में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कार्यक्रम को सांसद श्री भोजराज नाग ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ब्रेकिंग न्यूज राज्य के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में होंगे शामिल

राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2025 : उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम करें रोशन -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर: राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने जा रहे युवाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित बनाने की भारत सरकार की मुहिम में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। भारत मण्डपम नई दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष भारत को विकसित बनाने के विज़न को प्रस्तुत करने का अवसर राज्य के 75 युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि युवा दिल्ली में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आगामी 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ऐसा प्रदर्शन करें कि देश के अन्य राज्यो से आये युवाओं के जुबान पर "छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया" हो। खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे। गौरतलब है कि युवा महोत्सव के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया।

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 26 और 27 दिसम्बर 2024 को यूथ डॉयलाग सम्पन्न हुआ

रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 26 और 27 दिसम्बर 2024 को यूथ डॉयलाग सम्पन्न हुआ। भारत को पूर्णतः टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना, विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकास भी विरासत भी की थीम पर माई भारत पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख 26 हजार से अधिक पंजीकृत वालेंटियर्स एवं प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए सर्व प्रथम आनलाइन क्वीज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। आनलाईन क्वीज़ में क्वालीफाईड 6,103 युवाओं में से 635 युवाओं ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी निर्धारित 10 थीम पर निबंध लेखन किया। निबंध लेखन अंतर्गत प्रत्येक विषय में अधिकतम 25 अभ्यर्थियों का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया जाना था। इसमें से 228 युवाओं का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया गया।

स्टेट चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के 45 युवाओं का चयन

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर में स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य से 12 विषय विशेषज्ञों ने युवा प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत विज़न पी.पी.टी. का मूल्यांकन किया। स्टेट चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के 45 युवाओं का चयन कर उन्हें नई दिल्ली भेजने हेतु "Sending Off" समारोह का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन का विशेषज्ञों के माध्यम से वीडियो अवलोकन कर राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन लोकगीत, लोकनृत्य, कविता, कहानी, चित्रकला, साइंस मेला एवं वक्तृत्व कला विधाओं से चयनित किया गया है।

पेंगोलिन तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन तस्कर पकड़ाए

छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री श्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट श्री योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर श्री देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग श्री बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) श्री लल्लन जी तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्री श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक श्री चौतन सिंह कश्यप, कु. शारदा मण्डावी, श्री शंकर सिंह बघेल, श्री गोपाल नाग, श्री राम सिंह बघेल, श्री कैलाश नागेश, कु. कविता ठाकुर, श्रीमती कुन्ती कश्यप, श्रीमती जया नेताम, श्रीमती सोनमती, श्रीमती चंद्रीका राणा, श्रीमती दीपा पटेल, श्री उमर देव कोर्राम, श्री कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : छोटे व्यवसायों की उम्मीदों को मिला पंख

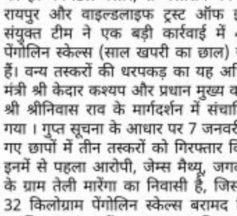

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित हो रही है। बिलासपुर जिले में इस वर्ष अब तक 11,036 हितग्राहियों को योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया है। उन्होंने पहले 10,000 रुपये का ऋण लेकर व्यवसाय में लगाया। समय पर ऋण चुकाने के बाद उन्हें 20,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और अपनी आय को बढ़ाने में कामयाब हुए है। श्री गुप्ता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे छोटे व्यवसायियों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। इसी तरह, मसानगंज निवासी श्री असद अख्तर खान, जो फास्ट फूड का ठेला चलाते हैं, ने बताया कि योजना से मिली ऋण राशि ने उनके व्यवसाय को नई ऊंचाई दी। उन्होंने कहा कि इस योजना ने उनकी आय बढ़ाने और व्यवसाय को मजबूत करने में मदद की है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। यह योजना फुटकर व्यवसायियों, रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर व्यवसाय करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। योजना के तहत प्रथम चरण में 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। द्वितीय चरण में समय पर पहला ऋण चुकाने पर 20,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। तृतीय चरण में दूसरा ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये का ऋण प्रदाय किया जाता है। योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को व्यवसाय में मदद करना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। बिलासपुर जिले में इस योजना के तहत अब तक प्रथम ऋण के लिए 8,123 लक्ष्य में से 7,944 आवेदन स्वीकृत हुए और 7,591 हितग्राहियों को ऋण दिया गया। द्वितीय ऋण के तहत 3,673 लक्ष्य में से 2,398 आवेदन स्वीकृत हुए और 2,207 हितग्राहियों को राशि प्रदान की गई। तृतीय ऋण के लिए 330 लक्ष्य के विरुद्ध 975 आवेदन आए, जिनमें से 694 स्वीकृत हुए और 559 हितग्राहियों को ऋण मिला। इस योजना का क्रियान्वयन नगर निगम की शहरी आजीविका मिशन द्वारा किया जाता है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति होगी लागू

रायपुर: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें। बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

पीएम जनमन योजना से पहाड़ी अंचलों में बिरहोर बसाहटों तक पहुंचने लगी है पक्की सड़क

Koytur times

धरमजयगढ़:पहाड़ीअंचलोंमेंबसेविशेषपिछड़ीजनजाति बिरहोरपरिवारोंकेउनकीसामाजिक,आर्थिकवशैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संचालित पीएम जनमन योजनाउनकेजीवनमेंसकारात्मकबदलावलेकरआरहीहै। अबतकसमाजकीमुख्य धारासेनहींजुड़पाएइनबिरहोर बसाहटोंतकअबपक्कीसड़कपहुंचनेलगीहै।येसड़केंइन बिरहोरपरिवारोंकेसर्वांगीणविकासकीनईराहेंखोलेंगी।

यहां रहने वाले निवासियों को अब सुकून है कि बारिश के दिनों में कच्ची सड़कों से होने वाली समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगी। रायगढ़ जिले के आदिवासी बहुल धरमजयगढ़ ब्लॉक के बसंतपुर के बिरहोर श्री गोविन्द और रामविलास ने बताया कि अब गांव में पक्की सड़क बन जाने से आवागमन में सुविधा मिल रही है। पहले पहाड़ी एरिया एवं कच्ची सड़कों के कारण गांववासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खासकर बारिश के दिनों में जब किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी, तो कच्ची सड़कों के चलते एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुँच पाती थी। इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि रास्ते की स्थिति खराब थी। अब सड़क के निर्माण से इन सभी समस्याओं का हल निकला है और लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को यहां गांव में पक्की सड़क निर्माण कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर बसाहटों तक पक्की सड़क बनाने न्यूनतम आबादी का मापदण्ड किया गया शिथिल गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़कें बनवायी जा रही है। इस योजना के तहत बनने वाली सड़कें सामान्य बसाहट में 500 से अधिक आबादी और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले बसाहटों को योजना से जोडऩे का प्रावधान रहा है। लेकिन पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति की बसाहट को बारहमासी सड़कों से जोडऩे के लिए जरूरी आबादी के संख्या को शिथिल किया गया। अब 100 से अधिक आबादी वाले इन विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों के लिए पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें वर्तमान में 4 अन्य सड़कों का काम जारी है। इन सड़कों के पूरा होने से इन गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान होगी। उनके बच्चों को पढऩे-लिखने के लिए बाहर आने-जाने में सुविधा होगी। खेती-किसानी के लिए कृषि उत्पादों का परिवहन और विकासखण्ड और जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर ग्रामवासियों का आवागमन सुगम होगा।

अब तक 375 करोड़ की राशि की जा चुकी है जारी

रियलिटी शो बिग के सेट पर

श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के सीधे खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व व श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री श्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में शाम 4 बजे 37 हजार 355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित करेंगे। इसी तरह पंजीकृत 15 ई-रिक्शा धारकों को एक-एक लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

गुलाब की खेती से महक रहा है एबी अब्राहम का जीवन आस-पास के शहर अंबिकापुर, अनूपपुर तथा बिलासपुर में किया जा रहा गुलाबों की सप्लाई

एमसीबी: आज के समय में पारंपरिक खेती की तुलना में बागवानी या फूलों की खेती किसानों के लिए अधिक मुनाफा देने वाली खेती साबित हो रही है। गुलाब की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि गुलाब की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है और त्यौहारों, शादी समारोह व विभिन्न आयोजनों के समय इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत लालपुर में रहने वाले एबी अब्राहम ने गुलाब की खेती करके एक मिसाल कायम की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं। उनकी सफलता की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे पारंपरिक खेती से हटकर नए क्षेत्रों में प्रयास करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आस-पास के इलाके में डच रोज़ की खेती शुरू करने वाले किसानों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। यह दर्शाता है कि फूलों की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। एबी अब्राहम बताते हैं कि वर्तमान समय में किसान को बेमौसम बारिश, तूफान, अतिवृष्टि, सूखा जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है साथ ही विभिन्न प्रकार के कीटों व बीमारियों से अपनी फसलों की रक्षा करनी पड़ती है। इतनी परेशानियों के बाद भी किसान को अपेक्षाकृत अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। उनके द्वारा पूर्व में भी अपनी जमीन पर धान की फसल लगाया जाता था, जिससे उन्हें अधिक आमदनी नहीं होती थी। एबी अब्राहम ने परम्परागत कृषि से अलग आधुनिक खेती कर अपनी आय में वृद्धि करने की सोची। इसी दौरान लाभार्थी को नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा डच रोज़ की खेती की जानकारी मिली। डच रोज़ कल्टीवेशन से लंबे समय तके होने वाले लाभ की सोच से उन्होंने इसका खेती करने का निश्चय किया और अपने जमीन पर पाली हॉउस तैयार कर गुलाब की खेती प्रारंभ की। उद्यानिकी विभाग द्वारा उनके हौसले को बढ़ाते हुए समय पर दस्तावेजों की पूर्ति कराई गई और समय समय पर विभाग द्वारा एबी अब्राहम को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। एबी अब्राहम द्वारा फरवरी 2024 में लगभग अपने 1 एकड़ जमीन पर पॉली हाऊस का निर्माण कराकर डच रोज़ की खेती प्रारंभ की है। जहां उन्होंने इसकी 40,000 पौधे का प्लांटेशन किया। पॉली हाऊस के अंदर डच रोज़ की खेती करने से पौधों को सीधे सूर्य की रौशनी, बारिश, आंधी से सुरक्षा मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई और टपक विधि से कम पानी में गुलाब की खेती में सफलता प्राप्त हो रही है। एबी अब्राहम द्वारा किए गए गुलाब की खेती को देखने के लिए दूर-दूर से लोग भी आते हैं। एबी अब्राहम की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, कि कैसे एक किसान ने अपनी मेहनत और सोच के बल पर अपने आय में वृद्धि की और अपने जीवन को बेहतर बनाया। गुलाब के उत्पादन के शुरुआत से ही बाजार में इसकी मांग आने से एबी अब्राहम का उत्साह बढ़ा हुआ है। वे कहते हैं कि विभागीय मदद से उन्होंने डच रोज की खेती करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसका अब उन्हें लाभ मिल रहा है। वर्तमान में उनके द्वारा आस-पास के इलाके जैसे बिलासपुर, अम्बिकापुर में फूलों का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइजर, डेकोरेशन शॉप्स वालों से भी संपर्क किया जा रहा है, जिससे आगे चलकर बड़े पैमानों पर गुलाब का विक्रय किया जा सके। आने वाले त्यौहारों व शादी सीजन में बाजारों में फूलो की मांग बढ़ेगी, जिससे उनके आय में और अधिक वृद्धि होगी। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक किसान अपनी मेहनत और सोच के बल पर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है।

छत्तीसगढ़ के सनावल को झारखंड से जोड़ेगा कन्हर नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने के लिए कन्हर नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल स्थानीय लोगों के आवागमन को आसान करेगा। लगभग 15.20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। पुल के शुरू हो जाने से क्षेत्र के लगभग 20 गांवों की 40 हजार से अधिक आबादी को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। सनावल क्षेत्र के लोग रोजमर्रा की खरीदारी और इलाज के लिए झारखंड के गढ़वा, नगर उटारी और धुरकी शहरों पर निर्भर हैं। अभी इन शहरों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पुल बनने के बाद यह दूरी आधी हो जाएगी। धौली से गढ़वा की वर्तमान दूरी 100 किलोमीटर से घटकर 55 किलोमीटर रह जाएगी। धौली से नगर उटारी की वर्तमान 70 किलोमीटर की दूरी घटकर 35 किलोमीटर हो जाएगी। पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे न केवल व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच आवागमन भी सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के बालचौरा के बीच इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अभी तक 12 पियर और दो अबटर्मेंट में से पांच पियर और एक अबटर्मेंट का काम पूर्ण हो गया है। शेष कार्य तेजी से पूर्णतः की ओर है, इसे जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर जैसे 20 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, झारखंड के गढ़वा, नगर उटारी और धुरकी आने-जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा होगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-सीमा के भीतर इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह पुल न केवल क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत करेगा।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल

सखी सहेली समूह ने मछली पालन से बदली जिंदगी

सकारात्मक परिणाम सखी सहेली स्व-सहायता समूह के प्रयासों से साफ झलकता हुआ

मुंगेली मुंगेली जिले के शुक्लाभाठा-विचारपुर गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सखी सहेली स्व-सहायता समूह के प्रयासों में साफ झलकता है। समूह की महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेतगंगा ग्रामीण बैंक से छह लाख रुपए का ऋण लेकर मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बाई गबेल ने बताया कि पहले महिलाएं केवल खेती-बाड़ी पर निर्भर थीं। कम आमदनी के कारण घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। समूह से जुड़ने और शासन की चक्रीय निधि के तहत 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद उन्होंने बैंक से ऋण लेकर मछली पालन व्यवसाय शुरू किया। धीरे-धीरे व्यवसाय को विस्तार देते हुए अब वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गई हैं। समूह की महिलाओं की इस सफलता ने न केवल उनकी जीवनशैली में सुधार किया है, बल्कि वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। समूह की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता शासन की योजनाओं और उनके सही क्रियान्वयन का परिणाम है। सखी सहेली समूह की यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो अपने जीवन को बदलने की दिशा में प्रयासरत हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से संवर रही विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की जिंदगी

कोण्डागांव: जिले के दूरस्थ विकासखण्ड बड़ेराजपुर से 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोसमी के चनाभर्री जहां विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के 10 कमार परिवार निवासरत हैं। ग्राम पंचायत कोसमी अन्तर्गत चनाभर्री बसाहट वनग्राम में आता है, जो जंगल से लगा हुआ है। इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वनोपज पर आधारित हैं, जिससे वे अपना गुजर-बसर करते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (जनमन) अंतर्गत चनाभर्री को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बसाहट के रूप में चिन्हाकित कर यहां निवासरत सभी 10 कमार परिवारों को केंद्र एवं राज्य शासन की सभी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से योजना के बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है। चनाभर्री निवासी श्री गंगाराम मरकाम उन्हीं कमार जनजाति परिवारों में से एक हैं, जिन्हें जनमन योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास का लाभ मिला है। गंगाराम आज पक्का आवास पाकर बहुत खुश हैं और इससे उनके जीवन में एक बदलाव की शुरुआत हुई है।

रेशम के धागों से बुनी समृद्धि की कहानी, कोसा पालन बना आदिवासी किसानों की आर्थिक तरक्की का जरिया

जशपुर, छत्तीसगढ़: आदिवासी बहुल क्षेत्र टांगरगांव में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यहां के किसान अब रेशम विभाग की कोसा पालन योजना के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। परशु राम, राजकुमार, सुभाधर और अगस्तुस जैसे किसानों ने इस योजना को अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। कुछ साल पहले तक, टांगरगांव के ये किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर थे। सालभर की मेहनत के बाद भी केवल 30-35 रूपए हजार ही बचा पाते थे। परिवार चलाना मुश्किल था, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर जीवन के सपने अधूरे लगते थे। लेकिन, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रोजगारोन्मुख योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए रेशम विभाग ने कोसा पालन योजना को टांगरगांव में लागू किया। 5 हेक्टेयर वनभूमि पर साजा और अर्जुना के पौधे लगाए गए। इन पौधों पर कोसा कीट पालन कर किसानों को न केवल रोजगार का अवसर मिला, बल्कि उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2024-25 में टांगरगांव के इन किसानों ने 3000 डीएफएल्स (डिंबों) का पालन किया और 1,51,080 कोसाफल का उत्पादन किया। इस उत्पादन से कुल 5 लाख 20 हजार से अधिक की आमदनी हुई। प्रत्येक किसान को औसतन 1.50 लाख रूपए की वार्षिक आय प्राप्त हुई। इस अतिरिक्त आय ने न केवल इन किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि उनके परिवारों में भी खुशहाली लायी है। बच्चों को अब अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिल रही है। पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है। पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े और जरूरतें पूरी हो रही हैं। मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में जाने की मजबूरी खत्म हो गई है। परशु राम और उनके साथियों ने बताया, 'कोसा पालन योजना ने हमारी जिंदगी बदल दी है। पहले जो सपने देखना भी मुश्किल लगता था, अब वे पूरे हो रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल भेज पा रहे हैं। अब हमारे पास रोजगार है, आय है, और भविष्य के लिए उम्मीदें हैं। रेशम विभाग किसानों को उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहा है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। इस योजना के कारण जिले में मजदूरी के लिए पलायन में 75 प्रतिशत की कमी आई है। रेशम विभाग की इस योजना ने आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास का नया मॉडल पेश किया है। टांगरगांव के ये किसान अब न केवल आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बल्कि उनकी कहानी अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन रही है। रेशम के नाजुक धागों से बुनी यह सफलता की कहानी साबित करती है कि सही योजना और मेहनत से बड़े बदलाव संभव हैं। कोसा पालन ने इन किसानों को सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि एक नया जीवन भी दिया है। अब टांगरगांव के ये किसान न केवल अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की नींव भी रख रहे हैं।

शासन की मंशानुरूप योजनाओं का आम जन को लाभ मिले, समय समय हितग्राहियों से संपर्क कर फीडबैक लें अधिकारी - संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा

संवाददाता | अम्बिकापुर

अम्बिकापुर: सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में बुधवार को संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवपदस्थ संभागायुक्त ने शासन की मंशानुरूप महत्वकांक्षी शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय समय पर स्वयं हितग्राहियों से संपर्क कर फीडबैक लें जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन हो सके। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों का सघन निरीक्षण कर अधीनस्थों को शासन द्वारा निर्धारित कार्यालयीन समय पर कार्यालयों में उपस्थित रहें और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फील्ड भ्रमण पर फोकस करें। संभागायुक्त ने अधिकारियों को प्रशासनिक कसावट लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड भ्रमण के साथ विभाग आगामी 3 महीने का लक्ष्य निर्धारण करें जिसके अनुरूप विभाग द्वारा विकास की उपलब्धि हासिल की जाएगी। इसी तरह उन्होंने चार वर्षीय कार्ययोजना भी तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस पैरामीटर बनाएं जिसके आधार पर योजनाओं और कार्यक्रमों में अपने परफॉर्मेंस का आकलन करें। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण, मानव संसाधन संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, कानून व्यवस्था, योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुंचाना और योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपायुक्त विकास श्री आरके खूंटे एवं समस्त संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषक जीवन ज्योति योजना से भूमि हुई सिंचित मल्टी क्रॉप लेकर किसानों ने की अपनी आय में वृद्धि

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में गांवों में कृषक जीवन ज्योति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसकी क्रम में सूरजपुर जिले के विकासखण्ड सूरजपुर के ग्राम पचिरा में इस योजना के क्रियान्वयन से आज 15 किसान वर्ष में एक से ज्यादा फसल अपने खेत में ले रहे है। साथ ही साथ वे सब्जी की भी खेती कर रहें है। जिससे न केवल उनके आय में वृद्धि हुई है बल्कि वह आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत भी बने हैं। गौरतलब है कि रेहण नदी के किनारे स्थित ग्राम में 15 किसानों का जमीन होने के बावजूद भी उनकी यह भूमि सिंचित नहीं हो पा रही थी। किसानों के कृषि भूमि के पास विद्युत लाइन का विस्तार नहीं होने के कारण यहां सिंचाई करना संभव नहीं हो पा रहा था एवं किसान केवल वर्षा में ही धान की खेती कर पा रहे थे। विद्युत विभाग अंतर्गत कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत इस क्षेत्र में पंप विद्युतीकरण करने का कार्य किया गया। इस योजना के तहत प्रति किसान के लिए विद्युत लाईन विस्तार हेतु लगने वाले लागत में 01 लाख रूपए छुट प्रदान किया जाता है। इस योजनांतर्गत 15 किसानों ने विद्युत विभाग के सूरजपुर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसके पश्चात विभाग ने तत्परता पूर्वक सर्वे कराकर विद्युत लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण कराया जिसमें 650 मी. 11 के.व्ही. लाईन् 1 नग 63 के.व्ही.ए का ट्रांसफार्मर एवं 1200 मी. एल.टी. लाईन का विस्तार शामिल था। वर्तमान में सभी किसानों के खेत रेहण नदी के किनारे विद्युतीकृत है एवं सभी किसानों को वर्षभर सिंचाई हेतु सुविधा प्रदान किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र के किसान बेहद खुश हैं।

कलेक्टर ने किया जिले के धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण

संवाददाता | नारायणपुर

राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर जिले में 17 धान खरीदी केन्द्र बनाया गया है, जहां पर सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर प्रतिष्ठ ममगाईं ने धान खरीदी केन्द्र गढ़बेंगाल और बाकुलवाही का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान बेचने आए कृषकों से चर्चा करते हुए धान खरीदी केंद्र में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कृषकों से सोसायटी में बारदाने की उपलब्धता, धान की गुणवत्ता, टोकन काटने की प्रक्रिया और किसानों को दी जानी वाली भुगतान की जानकारी ली और बारदाना गोदाम, धान बोरे की स्टेकिंग, ड्रेनेज और पेयजल की व्यवस्था संबंधी जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाए दुरूस्त करने के निर्देश दिये। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 14 नवंबर से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर ने गढ़बेंगाल धान खरीदी केन्द्र में धान बेचने आए गरावंड़ के किसान धनीराम उईके से धान उत्पादन संबंधी जानकारी लेते हुए ऋण लेने सहित बारदाने के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर के द्वारा किसान धनीराम के धान का सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने धान उपार्जन केन्द्र में धान बेचने आए कृषकों से चर्चा करते हुए धान खरीदी हेतु की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लिया। गढ़बेंगाल धान खरीदी केन्द्र में 873 किसान पंजीकृत हैं, उनमें से 663 किसानों ने अब तक धान की बिक्री किये हैं। अब तक किसानों से 32125.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जिसमें से खरीदी केन्द्र से 13460 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। आज 26 किसानों को टोकन दिया गया है, वे धान का विक्रय करेंगें। कलेक्टर ने से धान उठाव के संबंध में हमालो की जानकारी ली खरीदी केन्द्र प्रभारी ने बताया की 12 हमाल की व्यवस्था किया गया है।

कलेक्टर ने गढ़बेंगाल धान खरीदी केन्द्र के निरीक्षण पश्चात् खरीदी केन्द्र बाकुलवाही धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान खरीदी केन्द्र में नमी मापक यंत्र से किसानो के धान को नमी का जांच किया गया। कलेक्टर ने धान बेचने आए ग्राम गुमियापाल के किसान बलदेव से चर्चा करते हुए बारदाने के बारे में पूछा और प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के संबंध में जानकारी ली। बाकुलवाही धान खरीदी केन्द्र में 959 किसान पंजीकृत हैं, उनमें से 597 किसानों ने अब तक धान की बिक्री किए हैं। अब तक किसानों से 25820.40 क्विंटन धान की खरीदी की गई है, जिसमें से खरीदी केन्द्र से 7097.97 क्विंटल धान का उठाव किया गया है।

कार्यों में लेट लतीफी व लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: मंत्री श्री केदार कश्यप

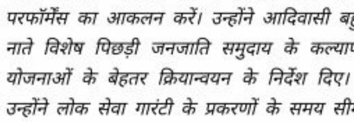

रायपुर: जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही निविदा की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय-सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए, साथ ही उन्होंने समय-समय पर कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में मंत्री श्री केदार कश्यप ने पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जा सका । वाटर लिंकिंग योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए को प्रस्ताव भेजने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने हेतु ईओआई बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें। बैठक में मंत्री श्री केदार कश्यप ने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु डीपीआर शासन को प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जगदलपुर में जल्द खुलेगा मुख्य अभियंता कार्यालय बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन हो चुका है। तत्काल आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर बस्तर वासियों को मुख्य अभियंता कार्यालय प्राप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य जल सूचना केंद्र (स्टेट वॉटर इनफॉर्मेशन सेंटर) की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए 22 पदों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी हैं। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जायेगा । बैठक में जल संसाधन सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता श्री इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता श्री एस व्ही. भागवत, श्री के.एस गुरूवर, श्री एस.के.टीकम, श्री डी.के. उमेरकर, श्री आर. के. इंदवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रवासी भारतीय दिवस पर विशेष लेख: दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति 1.75 करोड़ हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समूह हैं

लेखक/विचारक
महेन्द्र सिंह मरपच्ची

प्रवासी भारतीय दिवस, जो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय समुदाय की विदेशों में सशक्त उपस्थिति और उनके योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन विशेष रूप से उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी थी। महात्मा गांधी का यह कदम भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई ऊर्जा और दिशा का प्रतीक बन गया। इस दिन के अवसर पर हम यह सोचते हैं कि भारत से बाहर बसे भारतीयों ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को दुनिया भर में फैलाया है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य से विदेशों में प्रवास और प्रवासी भारतीयों की स्थिति पर भी गौर करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़, जिसे हम अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानते हैं, में भी एक उल्लेखनीय संख्या में प्रवासी और शरणार्थी निवास करते हैं। राज्य में लगभग 63,000 विदेशी शरणार्थी रहते हैं, जिनमें से रायपुर, राज्य की राजधानी, शरणार्थियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यहां 2,700 से अधिक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में कई अन्य भारतीय राज्यों से आकर बसे लोग भी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बनाए हुए हैं। इन शरणार्थियों और प्रवासियों ने अपने संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद छत्तीसगढ़ में न केवल अपने जीवन स्तर को बेहतर किया है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विविधता को भी समृद्ध किया है।

राज्य में बसे इन प्रवासियों का योगदान स्थानीय समाज में महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कृषि, उद्योग, निर्माण और छोटे व्यापारों में इनका बड़ा हाथ रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने इन समुदायों को सहायक और सहिष्णुता का पर्याय बना लिया है। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में प्रवासियों और शरणार्थियों की स्थिति केवल आवास और रोजगार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत के भीतर आंतरिक प्रवासन की दर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और छत्तीसगढ़ इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 5.6 करोड़ भारतीय अपने जन्म के राज्य से अन्य राज्यों में प्रवास कर चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में प्रवासन शामिल है। विशेष रूप से, राज्य के आदिवासी समुदायों से लोग रोजगार, शिक्षा, और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में राज्य के शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। यह प्रवासन खासकर रायपुर, बिलासपुर, और दुर्ग जैसे विकसित शहरों में अधिक देखा जाता है। राज्य के भीतर और बाहर इस प्रकार का प्रवासन आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता का संकेत है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों से श्रमिकों का प्रवास, विशेष रूप से निर्माण, खनन और उद्योगों में, राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ रहा है। इसके अलावा, इस प्रवासन ने स्थानीय बाजारों में विविधता लाने का काम किया है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि इस प्रवासन के कारण कुछ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि शहरीकरण के प्रभाव, शिक्षा की कमी, और सांस्कृतिक संकट। फिर भी, इस प्रवासन को विकास के एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह राज्य की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम विदेशों में बसे भारतीयों की बात करें, तो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में विदेशों में बसे भारतीयों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई थी। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि भारतीय समुदाय की वैश्विक उपस्थिति कितनी प्रभावशाली हो रही है। हालांकि, छत्तीसगढ़ से विदेशों में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि इस राज्य के नागरिक विभिन्न देशों में अपने योगदान से भारतीय समुदाय की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, जो विदेशों में बसे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से भारत का नाम रोशन किया है और भारतीय संस्कृति को वहां के समाजों में फैलाया है।

विदेशों में भारतीयों की उपस्थिति आज बहुत ही विस्तृत और विविध है। भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी संख्या अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों में देखने को मिलती है। ये प्रवासी भारतीय विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, और कला में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। इसके अलावा, प्रवासी भारतीयों ने न केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार किया है, बल्कि अपने काम और मेहनत से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है।आज विश्व के कई देशों में शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के लोग आसीन हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय ज्ञान और श्रम की शक्ति वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च है। विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का योगदान केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय भोजन, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय त्योहारों की धूमधाम, और भारतीय कला ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है।

छत्तीसगढ़ से विदेशों में प्रवास की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन राज्य के भीतर और अन्य भारतीय राज्यों में प्रवासन एक सामान्य प्रवृत्ति है। भविष्य में, जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ के विकास और वैश्वीकरण के अवसर बढ़ेंगे, राज्य से विदेशों में प्रवास की दर में भी वृद्धि हो सकती है। यह राज्य के आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि प्रवासी भारतीय अपने साथ न केवल आर्थिक योगदान लाते हैं, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को भी फैलाते हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, और शिक्षा के क्षेत्र में विकास से यह संभावना बन सकती है कि अधिक लोग विदेशों में काम करने के अवसरों की तलाश करेंगे। इससे राज्य को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि प्रवासी भारतीयों के नेटवर्क से राज्य को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी मदद मिलेगी।

प्रवासी भारतीयों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विदेशों में बनाए रखने और प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे न केवल अपने परिवारों और समुदायों में भारतीय मूल्यों को संरक्षित रखते हैं, बल्कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को मजबूत करते हैं। प्रवासी भारतीयों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर सशक्त किया है और उन्होंने भारतीय व्यापारिक रिश्तों को न केवल औपचारिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी मजबूत किया है।

प्रवासी भारतीय दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि भारतीय समुदाय की वैश्विक पहचान को आकार देने में उन प्रवासी भारतीयों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो विदेशों में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रतीक बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बसे प्रवासी और विदेशों में बसी भारतीयों की संख्या के आंकड़े सीमित हैं, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उनका योगदान हमारी संस्कृति और आर्थिक विकास में अहम है। प्रवासी भारतीयों का संघर्ष और उनकी सफलता न केवल उनके अपने परिवारों और समाजों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि यह पूरे भारतीय समुदाय की सम्मानजनक उपस्थिति का प्रतीक है। हम सभी को यह अवसर मिला है कि हम अपने प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता दें और उनकी मेहनत को सराहें, जो उन्होंने विदेशों में बसे रहकर भारत की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य उन भारतीयों को सम्मानित करना है जिन्होंने विदेशों में रहते हुए भारतीय संस्कृति, परंपरा, और मूल्य प्रणाली को बनाए रखा और उसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। यह दिन 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी, जो स्वयं एक प्रवासी भारतीय थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।

दिल के लिए लाभदायक है स्टार फ्रूट

स्टार फ्रूट इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करता है। इससे रक्त संचार और हृदय गति सामान्य बनी रहती है। स्टार फ्रूट में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, बी-5, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फोलेट, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी लाभकारी होते हैं। स्टार फ्रूट एक लो कैलोरी वाला फल है, जिसमें एंटीऑक्सिडेंट की मात्रा अधिक होती है। इसके सेवन से शरीर को विटामिन सी मिलता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप कम बीमार पड़ते हैं। स्टार फ्रूट में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, जो सोरायसिस और म्यूकस की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें सोडियम और पोटैशियम पाए जाते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। यह फल शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करता है। इससे रक्त संचार और हृदय गति सामान्य बनी रहती है। स्टार फ्रूट फाइबर से भरपूर होता है। कम कैलोरी होने की वजह से यह मेटाबॉलिज्म को तेज बनाता है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिलती है। इसके सेवन से कब्ज और पेट से संबंधित अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। स्टार फ्रूट के सेवन से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

स्टार फ्रूट में प्राकृतिक यौगिक और ऑक्सलेट होते हैं, जो किडनी रोगियों के लिए हानिकारक होते हैं। यदि आप इससे संबधित किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो सेवन करने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें।

-पायल शर्मा, आहार विशेषज्ञ

संपादकीय प्रेम और मुक्ति का गहरा संबंध है

सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है

प्रेम एक अत्यंत अद्भुत और अलौकिक घटना है। यह साधारण नहीं, बल्कि स्वर्गीय स्वरूप वाला है। यह उस अदृश्य दिव्यता का प्रतीक है, जो इस पृथ्वी पर आकर अपना स्वरूप बनाती है। प्रेम वही है, जो अंधेरे में छिपी रोशनी के समान क्षणिक रूप में प्रकट होता है, वही प्रेम है, जो पथरीले हृदय में हल्के से नरम भाव लाता है। यह कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जो हमें बिना किसी कारण के एक दूसरे के जीवन में आनंदित होने की क्षमता देती है। प्रेम का कोई कारण नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम किसी को इसलिए प्रेम करते हैं, तो यह मोह का रूप होता है। वास्तविक प्रेम तो तब होता है, जब हमें इसका कोई कारण नहीं मिलता, और हम बिना किसी वजह के प्रेम करते हैं। यदि हमें यह महसूस होता है कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, तो यही असली प्रेम है। प्रेम का अस्तित्व केवल आकाश से उतरने जैसी एक अभिव्यक्ति है, जिसमें उसकी कोई जड़ें नहीं होतीं। जड़ें तो मोह में होती हैं, और यही कारण है कि मोह का एक स्वार्थी रूप होता है, जबकि प्रेम निराकार और निर्मोही होता है। प्रेम न तो किसी पर कब्जा करता है, न ही इसे किसी के कब्जे में आने की आवश्यकता होती है। यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो दो व्यक्तियों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और स्वच्छ आदान-प्रदान को जन्म देता है। प्रेम का मूल स्वरूप यही है कि इसमें कोई भी किसी का मालिक नहीं होता, और न ही कोई किसी का दासी बनता है। प्रेम कभी किसी के गले में बंधन नहीं डालता, बल्कि बंधनों को काटता है। जब प्रेम का अनुभव होता है, तो यह हमें और हमारे प्रियजन को मुक्ति का एहसास दिलाता है। प्रेम से मुक्ति मिलती है, और यही प्रेम की विशेषता है। ईश्वर की ओर से प्रेम की यह भावना जीसस द्वारा ईश्वर के रूप में व्यक्त की गई, बुद्ध ने इसे ध्यान की अंतिम परिणति के रूप में देखा, और महावीर ने इसे कैवल्य के स्वभाव के रूप में माना। लेकिन सामान्य मानव प्रेम में इतना कचरा और भ्रम होता है कि प्रेम का शुद्ध रूप मुश्किल से देखने को मिलता है। प्रेम के नाम पर घृणा छिपी होती है, और इसी कारण प्रेम जल्दी ही घृणा में बदल जाता है। प्रेम का असली रूप तो वह होता है, जिसमें प्रेम और घृणा का कोई स्थान नहीं होता। यदि प्रेम घृणा में बदल सकता है, तो इसका अर्थ है कि वह असली प्रेम नहीं था, बल्कि एक ढोंग था। प्रेम का असली रूप शुद्ध और निर्लिप्त होता है, जो कभी भी घृणा, शोषण, या किसी भी प्रकार की राजनीति या कूटनीति में नहीं बदलता। प्रेम वह स्वच्छ शिखा है, जो किसी भी धुएं को उत्पन्न नहीं करती। जैसे लकड़ियां सूखी होती हैं, वैसे प्रेम में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि प्रेम में गंदगी और मोह है, तो वह धुएं की तरह प्रदूषण फैलाता है, और यही कारण है कि प्रेम को निर्दोष और स्वच्छ रूप में रखना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आँखों को अंधा कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में उलझनें और क्रोध, जलन, या ईर्ष्या उत्पन्न कर रहा है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे प्रेम में बहुत अधिक कचरा भरा हुआ है। तुम्हें इस प्रेम को घृणा, जलन और ईर्ष्या से मुक्त करना चाहिए। तभी तुम महसूस करोगे कि तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही प्रार्थना का रूप बन जाएगा। प्रेम यदि पवित्र और निर्दोष होता है, तो वह अपने आप में एक उच्चतम प्रार्थना बन जाता है। प्रेम को ही प्रार्थना बनाना सबसे सुंदर रूप है।

रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की वीरता की प्रतीक

रानी दुर्गावती वीरता की एक साहस थी,
गोंडवाना की धरती पर सम्राज्ञी सर्वश्रेष्ठ महारानी थी ।
उनकी तलवारों से कभी न थमी थी तीरों की बौछार,
जब सम्राज्य की रक्षा हो, कभी न रुका था संघर्ष का पर्वाह।
धन्य है वो मातृभूमि, जिस पर उनका क़दम पड़ा,
माँ की तरह संजीवनी दी, वही जो कर्म का बंधन पड़ा।
भयानक युद्ध में, जहाँ जान का था खतरा हर पल,
रानी दुर्गावती की दृढ़ता से वीर बने सब दल।
संघर्ष से उभरती रही वो नारी, अनमनी नहीं,
हर एक कदम उनके जीवन का था इतिहास में महाकवि।
कभी न भागी किसी से, न डर के जिए,
सदैव सही रास्ते पर अपनी धरती की हिफाज़त की।
फड़ापेन के आशीर्वाद से मिली शक्ति अपार,
महारानी रानी दुर्गावती, भयंकर संघर्ष की थी पार।
अपने महल और प्रजा की रक्षा की दृढ़ संकल्प से,
नारी के साहस को बेमिसाल किया उन्होने हर पल से।
वह खड़ी थी चुनौती के लिए, न भटकी जीवन की राह,
हर लड़ाई में उनकी ताबड़तोड़ शक्ति ने खींची थी चांद की राह।
कभी न डरें वे दुश्मनों के सामने, रानी दुर्गावती, संघर्ष की बेमिसाल मिसाल बने।
अपने राज्य की स्वतंत्रता को सहेजा क़ीमत चुकाकर,
राजनीति की गूढ़ता को समझा, खुद को कभी न लहराकर।
सभी नायक उनके संघर्ष से प्रेरित हुए,
गोंडवाना के अंबर में दुर्गावती के उजाले से हर साया हुआ शुद्ध।
नारी शक्ति का अद्वितीय रूप रानी दुर्गावती,
धरती से लेकर आकाश तक उनकी महिमा में बसी बत्तियाँ।
हर युद्ध में वो विजय पाई, पर अपने स्वाभिमान से जी,
रानी दुर्गावती की वीरता की कथा सदा जीवन में चमकती रही।

संसद में पेश दोनों विधेयकों पर विचार के लिए हुई जेपीसी की पहली बैठक, भाजपा सदस्यों ने समर्थन किया, विपक्ष ने एक साथ चुनाव विधेयकों पर सवाल उठाए

नई दिल्ली: लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले दो विधेयकों पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक बुधवार को हुई, जिसमें सदस्यों के बीच जमकर तर्क-वितर्क हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के सांसदों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए और इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला करार दिया। इस बैठक में सांसदों को 18,000 से अधिक पृष्ठों का दस्तावेज दिया गया था, जिसमें कोविंद समिति की रिपोर्ट के सभी खंड और उसके 21 अनुलग्नक शामिल थे। दस्तावेजों की प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में थीं और इसके साथ एक सॉफ्ट कॉपी भी दी गई। यह 39 सदस्यीय समिति विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विधेयकों के प्रावधानों और औचित्य पर प्रस्तुतिकरण के बाद विचार विमर्श कर रही थी। भा.ज.पा. के सांसद संजय जायसवाल ने इस दौरान 1957 का उल्लेख किया, जब सात राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया था, ताकि इन राज्यों के चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के साथ एकसाथ कराए जा सकें। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तब के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया था। विपक्षी सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ थे और उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि यह एक ऐसी प्रक्रिया को लागू करने का प्रयास है, जिससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ेगा। यह बैठक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और संविधान की आत्मा के संरक्षण पर जोर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून पर विचार के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की है। अदालत ने यह कहा कि यह मामला, अनुच्छेद-141 के तहत, शीर्ष कोर्ट की राय बनाम विधायिका की कानून बनाने की शक्ति का मामला है। कोर्ट यह विचार करेगा कि इन दोनों में से किसकी राय ज्यादा अहम है। गैर-सरकारी संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ से कहा कि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यदि अदालत ने इस पर दखल नहीं दिया, तो नए कानून के तहत नए सीईसी की नियुक्ति हो सकती है। भूषण ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस चयन समिति से नहीं हटा सकती, जिसका गठन शीर्ष कोर्ट ने 2 मार्च, 2023 को किया था।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनाने का निर्देश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी और निष्पक्ष हो। लेकिन केंद्र सरकार ने इस समिति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया और 2023 में एक नया कानून पारित किया। इस मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सरकार के पास इस निर्णय से बचने का एकमात्र तरीका संविधान में संशोधन करना था, न कि नया कानून बनाना। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वह संविधान के प्रावधानों से मेल नहीं खाते। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई तय की है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि क्या सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए नए कानून के तहत आगे बढ़ सकती है, या इसे सुप्रीम कोर्ट की सलाह और निर्देश के तहत ही किया जाएगा।

ब्रेकिंग न्यूज़ गरीब नागरिकों को गिनी पिग के रूप में किया जा रहा है इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: गरीब देशों में होते हैं दवाओं और टीकों के क्लिनिकल परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि दवाओं और टीकों के क्लिनिकल परीक्षण अक्सर गरीब देशों में किए जाते हैं। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों पर आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे की दलीलों पर विचार किया।

दवे ने बताया कि नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों के लिए नियम 2019 में बनाए गए थे। इसके बाद, 2024 में औषधि और नैदानिक परीक्षण (संशोधन) नियमों को अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य रोगी सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और वैश्विक मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। एनजीओ स्वास्थ्य अधिकार मंच के वकील संजय पारिख ने 2012 में दायर जनहित याचिका में कहा कि गरीब नागरिकों को अभी भी "गिनी पिग" के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। पारिख ने आरोप लगाया कि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां देशभर में बड़े पैमाने पर नैदानिक दवा परीक्षण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में अपनी आपत्तियां और प्रस्तुतियां दर्ज कराना चाहते हैं, ताकि शिकायतों का उचित निवारण सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: देरी के कारण अपील खारिज नहीं की जा सकती

दूसरी एक अन्य केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी अपील को देरी के कारणों की जांच किए बिना, समय सीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज नहीं कर सकती। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में माना। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 मार्च 2023 के आदेश को गलत ठहराया, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महेश सिंह बंजारा की ओर से दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि और 10 साल की सजा के खिलाफ दायर अपील को देरी के कारण खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1,637 दिनों की देरी को माफ करते हुए मामले को हाईकोर्ट को वापस भेजा और कहा कि उसे मेरिट के आधार पर और कानून के अनुसार अपील की जांच करनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देरी के कारण अपील खारिज होने से उनकी दोषसिद्धि और सजा अंतिम हो जाएगी।

समय सीमा की बैठक सम्पन्न: जिला अधिकारी गणतंत्र दिवस की तैयारी करें प्रारंभ...कलेक्टर

एमसीबी: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने समय सीमा की बैठक के दौरान 26 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि समारोह का आयोजन आमाखेरवा ग्राउंड मनेंद्रगढ़ में किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के संदेश को समारोह स्थल पर उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाए। समारोह स्थल पर चिकित्सा दल और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ आमाखेरवा ग्राउंड की साफ-सफाई, ट्रैक लाइटिंग, टेंट, कुर्सी, बेरिकेटिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही दो सफेद टोपियां, एक सफेद छाता, माइक, राष्ट्रीय ध्वज, बांस-बल्ली के माध्यम से बेरिकेटिंग, जनसामान्य के लिए पेयजल हेतु पानी टैंकर/फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, सजावट के लिए गमलों और साज-सज्जा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही विद्युत की व्यवस्था, उद्घोषक की नियुक्ति, सफेद कबूतरों, गुब्बारों और बैण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। जिला पुलिस विभाग, होमगार्ड, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, वन रक्षक और कोटवार द्वारा पूर्ण गणवेश में मार्च पास्ट आयोजित करने के निर्देश दिए गए। और आमंत्रण पत्र की छपाई और वितरण, प्रशस्ति पत्र की तैयारी, रंगोली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/शहीद परिवारों के लिए लाने-ले जाने और रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परेड निरीक्षण के लिए खुली जिप्सी, उद्घोषक को कार्यक्रम की समय सूची पूर्व में उपलब्ध कराना, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की व्यवस्था, ध्वजारोहण, रिहर्सल, पुरस्कार वितरण, मिष्ठान वितरण, मंच स्थल पर स्वल्पाहार और झांकी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी तैयारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगे कहा कि जो किसान पहले धान समिति में दे रहे थे। किसी कारण से वंश अगर वो नहीं है तो उसका धान को खरीदी के लिए समिति को आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उनके परिवार के अन्य सदस्य धान बेच सके। एमसीबी जिला के पर्यटन स्थलों में टूरिस्ट के लिए वॉशरूम और रुकने के व्यवस्था हेतु जमीन आवंटन करने के लिए निर्देशित किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्री की बैठक वाली पीपीटी में पालन प्रतिवेदन को भरने, विभागों की साइड में योजनाओं की सही जानकारी डालने के लिए कहा गया और अनावश्यक चीजों को न डालने के लिए निर्देशित किया है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. अम्बिकापुर द्वारा एमसीबी जिला में 7 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कुंवारपुर (गड़वार), बरदर (खड़गवां), सिहगत (चिरमी), कौड़ीमार (खड़गवां), बंजी (चैनपुर), कटकोना (कोड़ा) और रतनपुर (जिल्दा) को बनाया गया है।

आगे उन्होंने कहा कि पुराने कार्यालयों में टॉयलेट की व्यवस्था तथा जमीन आवंटन, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के साथ विभागों को अर्बन का डेटा लॉगिन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी और एनएचएम को निर्देशित किया कि टूरिज्म बोर्ड को फोरलेन सड़क के हिसाब से लगाए ताकि दुबारा उखाड़ने की जरूरत न पड़े। इसके साथ ही कोई पुल निर्माण या अतिरिक्त निर्माण ठेकेदार को बिना विभागीय आदेश के पैसा भुगतान नहीं करने को कहा गया है। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नक्शा खसरा और सीमांकन को सही से करें। बिहारपुर में रोड से 500 मीटर दूर बकरी फार्म हेतु जमीन आवंटन के साथ पानी और बिजली की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, लिंगराज सिदार सहित अन्य जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

ईवाई का सुझाव: करदाताओं को राहत देने के लिए घटाई जाए कर दरों की संख्या बजट में नई व्यवस्था में टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करे सरकार

Koytur times | नई दिल्ली

केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में करदाताओं को राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था में टैक्स छूट सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, करदाताओं के लिए टैक्स दरों में भी कमी की संभावना जताई जा रही है, ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकें। अर्स्ट एंड यंग (ईवाई) इंडिया ने अपनी बजट पूर्व रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि सरकार को आगामी बजट में आयकरदाताओं को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, ईवाई ने यह भी कहा कि सरकार को 2023-24 तक 31 लाख करोड़ रुपये (जो कि जीडीपी का 9.6 फीसदी है) के आयकर विवाद को भी सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि विवादों से निपटने की प्रक्रिया तेज हो सके और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ सके। इसके अलावा, ईवाई इंडिया ने यह सुझाव भी दिया है कि करदाताओं को compliance बोझ से राहत देने के लिए पीएफ ब्याज दर (2.5 लाख रुपये से ऊपर) पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को निकासी चरण तक स्थगित किया जाना चाहिए। इससे करदाताओं को अपनी आय पर बेहतर नियंत्रण मिल सकेगा और उन्हें अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को अधिक लाभ मिल सके और देश की कर प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

सफलता की कहानी: अर्दन चेक डेम निर्माण से ग्रामीणों को सिंचाई और खेती में राहत

एमसीबी: जिले के ग्राम पंचायत बाला जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में अर्दन चेक डेम का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मिली है। लगभग 10 एकड़ भूमि को सिंचित करने में यह डेम मददगार साबित हुआ है। इस प्रकार के डेम का निर्माण स्थानीय समुदाय के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खासकर कृषि के लिए। इससे न केवल सिंचाई की सुविधा मिलती है, बल्कि यह जल संचयन में भी मदद करता है। इस क्षेत्र में अर्दन चेकडेम के निर्माण से स्थानीय किसानों को बहुत लाभ होगा और वे अपनी फसलों को बेहतर ढंग मेहनत करने वाले किसानों को जो संसाधन और सरकारी मदद मिलती है, तो उनकी मेहनत का सही फल मिलता है और उनकी तरक्की के नए रास्ते खुल जाते हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं से किसानों को मदद मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। बाला ग्राम पंचायत के पास करमबोथा नाला पर बनाए गए चेक डेम का उदाहरण इस बात को साबित करता है कि सही संसाधन और योजना से कृषि क्षेत्र में नवाचार और विविधता लाई जा सकती है। ग्राम पंचायत बाला की सफलता की कहानी बताती है कि जब ग्राम पंचायत और प्रशासन मिलकर काम करते हैं, तो तेज होती है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ग्राम पंचायत बाला ने ग्रामीणों की मांग पर एक कार्य का प्रस्ताव पारित किया, जिसे जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया गया और लगभग ढाई लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके बाद, ग्राम पंचायत को ही कार्य एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया।यह प्रक्रिया दर्शाती है कि ग्राम पंचायतें और प्रशासन के बीच सहयोग से स्थानीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्राम पंचायतें ग्रामीणों की समस्याओं को समझती हैं और उनका समाधान करने के लिए काम करती हैं।